

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर
समक्ष अशोक शिवहरे
सदस्य

पुनरावलोकन प्र० क० 283 / १११/२००९ विरुद्ध आदेश दिनांक ०६-१-२००९
पारित— द्वारा - सदरय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर — प्र०क० १५८४ ११/२००४

छिंगा पुत्रकाना काढी निवासी ग्राम धुवारा
तहसील विजावर, जिला छतरपुर, म०प्र०

आवेदक

विरुद्ध

म०प्र०शासन द्वारा

अनावेदक

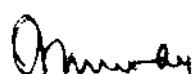
आवेदक के अभिभाषक श्री ए.के.अग्रवाल
अनावेदक की ओर से पैनल अभिभाषक

आदेश

(आज दिनांक १२-६-२०१४ को पारित)

यह पुनरावलोकन आवेदन निगरानी क्रमांक १५८४-११/२००४ में
तरका, सदस्य द्वारा पारित आदेश दिनांक ०६ जनवरी, २००९ के विरुद्ध मध्य
प्रदेश भू राजरव संहिता, १९५९ की धारा ५१ के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

२/ प्रकरण का रारॉश यह है कि पटवारी हलका नंबर १० ने नायव
तहसीलदार वृत्त धुवारा को प्रतिवेदन दिनांक ९-२-२००० प्रस्तुत कर बताया कि
आवेदक द्वारा ग्राम धुवारा की भूमि खसरानंबर २४८१ में सागर टीकमगढ़ सड़क
सीमा के अन्दर ३४x१३ फुट भूमि में सातह से ८ फुट दीवाल बनाकर मकान
निर्माण किया जा रहा है। नायव तहसीलदार धुवारा ने आवेदक के विरुद्ध
प्रकरण क्रमांक ३०९/अ-६८/९९-२००० पंजीबद्ध किया तथा जाच एवं सुनवाई
उपरांत आदेश दिनांक १६-५-२००० पारित कर आवेदक पर ५००/- रु
अर्थदण्ड करते हुये बेदखली का आदेश दिया। इस आदेश के विरुद्ध
अनुविभागीय अधिकारी, विजावर के समक्ष अपील होने पर प्र०क० ५०/०१-०२
में पारित आदेश दिनांक २-७-०२ से अपील समयवाह मानकर निरस्त की गई।



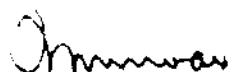
इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 759/01 02 में पारित आदेश दिनांक 9-11-04 से अपील निरस्त की गई एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 2-7-02 स्थिर रखा गया। अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के आदेश दिनांक 9-11-04 के विरुद्ध राजस्व मण्डल म0प्र० ग्वालियर में निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 1584- 11/2004 निगरानी में तत्का. सदस्य द्वारा पारित आदेश दिनांक 06 जनवरी, 2009 से निगरानी निरस्त की गई, इसी आदेश के विरुद्ध यह पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

2/ उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विवार किया गया तथा निगरानी क्रमांक 1584- 11/2004 में तत्का. सदस्य द्वारा पारित आदेश दिनांक 06 जनवरी, 2009 के अवलोकन के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया गया।

3/ राजस्व मण्डल, म0प्र० ग्वालियर में निगरानी क्रमांक 1584- 11/2004 में पारित आदेश दिनांक 06 जनवरी, 2009 में निर्णीत किया गया है कि ..

“यदि दिनांक 16-7-2000 को पारित आदेश की जानकारी उक्त तिथि को आवेदक को नहीं थी, किन्तु दिनांक 14.8.2000, 25-9-2000, 5-10-2000, 17-10-2000, 30-10-2000, 9-11-2000, 20-11-2000, 8-12-2000 तथा 21-12-2000 को विचारण न्यायालय में बेदखली की कार्यवाहियों में उसने भाग लिया है। अतः विद्वान् अनुविभागीय अधिकारी ने यह निष्कर्ष निकालकर कि अपीलार्थी को विचारण न्यायालय के आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 14-8-2000 को हो चुकी थी, कोई भूल नहीं की है। विलम्ब क्रमा करने के आवेदन में जो तथ्य बतलाये गये वे प्रकरण की वस्तुरिथ्ति के अनुसार नहीं होने से विद्वान् अनुविभागीय अधिकारी ने उनका समय सीमा अधिनियम के अधीन विलम्ब क्रमा करने का आवेदन सही तौर पर अमान्य किया है। असत्य भाषण कर उदारता का अपेक्षा न्यायालय से करना अनुचित कार्यवाही की परिधि में आता है।”

आदेश दिनांक 6 जनवरी 2009 में निकाले गये उक्त निष्कर्ष के विपरीत आवेदक के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके, आदेश दिनांक 6 जनवरी 2009 गे कौनसी प्रत्यक्ष भूल अथवा लिपिकीय भूल हुई है, जिसके आधार पर पुनरावलोकन आवेदन ग्राह्य किया जाकर तत्कालीन सदस्य, राजस्व मण्डल

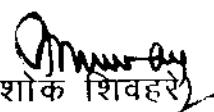


व्दारा निगरानी क्रमांक 1584-11/2004 में पारित आदेश दिनांक 06 जनवरी, 2009 में हस्तक्षेप किया जावे। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 को धारा 51 में पुनरावलोकन हेतु निम्नानुसार आधारों का स्पष्ट होना विचार हेतु जरूरी है:-

- (अ) किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक तत्परता के पश्चात् भी उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके व्दारा पेश नहीं की जा सकती थी या ,
- (ब) गामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या
- (स) कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

पुनर्विलोकन वाहे स्वप्रेरणा से किया जाय, या किसी पक्षकार के आवेदन पर, इन तीनों में से एक या अनेक आधारों पर ही किया जा सकता है अन्यथा नहीं, किन्तु आवेदक के अभिभाषक पुनरावलोकन आवेदन में अथवा बहस के दौरान ऐसा कोई समाधानकारक आधार नहीं बता सके कि उपरोक्त तीन आधारों में से एक अथवा उससे अधिक आधार पुनरावलोकन किये जाने हेतु उपलब्ध है।

4/ अतएव पुनरावलोकन आवेदन ठोस आधारों पर आधारित न होने अमान्य किया जाता है। परिणामतः तत्कालीन सदस्य, राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर व्दारा निगरानी क्रमांक 1584-11/2004 में पारित आदेश दिनांक 06 जनवरी, 2009 यथावत् रहता है।


(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर